and you may try to sell out the country by inviting foreigners. But you will find here at the grass-roots level the people will resist which is why this is where I end. I will make three simple propositions to the Government. I am sorry that the Finance Minister is not here. Number one, I want to tell him, "Please do not insist on pushing the Insurance Authority Bill either in this House or in the Lok Sabha. You will not have a parliamentary majority." I can say this with a full sense of responsibility. I will say the same thing about the kind of things that you have in mind about the power sector and the oil sector. It is extraordinary. In the oil sector what have you done in the past five years? Thirteen developed oilfields developed by the Oil and Natural Gas Commission and the Indian Oil Corporation, you handed over to the private sector and foreign investors. You also handed over 30 other development blocks to the private sector and the foreign sector. What is the result? There is a negative rate of growth. The more you have invited the private and foreign sectors, the higher is the fall in the production. All kinds of things are said. I do not want to go into these very unsavoury things including such statements that if there is a decline in the rate of production, very good, we can buy crude petroleum at the spot-market in the Gulf area. That would mean that somebody's commission would get inflated. These are the things which we cannot take lightly because facts have been revealed over the years. So, I would not want to say any thing more. I would only appeal to the Finance Minister. It is no use running after the will—o'—the—wisp. The foreigner won't come. We have to develop on our own on the basis of our own strength and with the help of our own resources. There is no escape. We can always strive to have an alternative model of dependent capitalism. India is too big a country and the burden of such a big country, no foreigner will be in a position to bear. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): There is a message from Lok Sabha. The Secretary-General will read it out.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL, 1997

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Income-tax (Amendment) Bill, 1997, as passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th March, 1997.
>
> The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE BUDGET (GENERAL), 1997-98—Contd.

श्री ओ० पी० कोहली (दिल्ली): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था उसकी प्रशंसा और वाह-वाह का दौर अब थम गया है और अब उस बजट को बहुत नजदीक से देखने पर उस बजट के नकारात्मक पहलू उभरकर आ रहे हैं तथा यह बात ध्यान में आ गयी है कि इस बजट के प्रशंसक कौन है। इस बजट के प्रशंसक समाज के सम्पन्न और ऊपर के वर्ग के लोग है। समाज का अपर क्लास इस बजट का प्रशंसक है। यह बजट अमीरों का बजट है, उद्योगपतियों का बजट है, शहरी सम्पन्न वर्गों का बजट है। विदेशी निवेशकों का बजट है। इस बजट में आम आदमी कहीं केन्द्र में नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि मेरे इस बजट का आधार कामन मिनिमम प्रोग्राम है और कामन मिनिमम प्रोग्राम गरीब आदमी की दुहाई देता है। लेकिन वह गरीब आदमी इस सारे बजट में से गायब है। दावा किया गया

है कि यह बजट ग्रोथ ओरियंटेड है। लेकिन ग्रोथ किस तरीके से? और यह ग्रोथ किसके लिए? अभी श्री अशोक मित्रा बतला रहे थे कि ग्रोथ को कैलकुलेट करने का, गणना करने का भी एक कुशल तरीका हो सकता है जिससे ग्रोथ रेट को अतिरंजित करके दिखाया जा सकता है। इसलिए सवाल पैदा होता है कि ग्रोथ ओरियंटेड बजट होने का दावा चाहे किया गया है पर यह ग्रोथ रेट कितना विश्वसनीय है, इस ग्रोथ रेट को मापने का पैमाना कितना विश्वसनीय है और यह सारा ग्रोथ किसके लिए है?

राजा चेलैया ने यह बात सही ही कही है कि —

This Budget ushers us in capitalism without any safeguards.

गरीब आंख से ओझल किया गया है। देश में कितने गरीब है? गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? इसका भी अभी ठीक-ठीक कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हो पाया है। किसी एक मानदण्ड को अपनाया जाता है तो उसके हिसाब से गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की एक संख्या निकलती है और कभी दूसरा मापदण्ड अपनाया जाता है तो गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की संख्या का आंकड़ा दूसरा निकलता है। 107 मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं या 320 मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं — जब तक गरीबी का ठीक-ठीक आंकड़ा हमारे सामने नहीं होगा तब तक गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए किसी प्रकार के बजट की कल्पना भी हम नहीं कर सकते।

बड़ी अजीब बात है कि बजट में कास्मैटिक्स और एयर कंडीशनर पर तो एक्साइज ड्यूटी कम की गयी है और इन पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है यह समझ से बाहर की बात है। बजट प्रस्तावों का कुल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका वित्त मंत्री ने कोई विश्लेषण और विवेचन नहीं किया है। बहुत चतुराई से वह बजट प्रस्तावों के इंपैक्ट के विश्लेषण और विवेचन को बचा गए। "एक्सप्रैस इन्वेस्टमेंट वीकली" ने एक आकलन किया है जिसके हिसाब से निगम कर में हमको इन बजट प्रस्तावों के कारण 6387 करोड़ रुपये की क्षति हो सकती है। आयकर में बजट प्रस्तावों के कारण 7568 करोड़ रुपये की क्षति हो सकती है। सीमा शुल्क में एक 17 हजार 242 करोड़ रुपये की क्षति हो सकती है। अब यह जो बजट प्रस्तावों के कारण क्षति होगी इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी, उसके स्रोत क्या होंगे, वित्त मंत्री इस विषय में मौन धारण किए हुए हैं। एक ओर इन बजट प्रस्तावों के कारण होने वाली बड़ी क्षति और दूसरी ओर वित्त मंत्री जी का बड़ा स्वप्रिल आशावाद की राजस्व वसूली में कमी नहीं होगी, राजस्व वसूली बढ़ जाएगी एक बहुत विचित्र किस्म के तर्क पर उनका यह स्वप्रिल आशावाद टिका हुआ है और यह तर्क यह है कि रियायतें दो, राजस्व वसूली अधिक होगी। लेकिन न अपने देश का, न विदेशों का अनुभव उनके इस आशावाद का कोई समर्थन करता है। राजस्व वसूली में वृद्धि के लिए आवश्यकता है कि हमारा कर प्रशासन मजबूत हो। हमारा मौजूदा कर प्रशासन, आय कर प्रशासन कमजोर है, अक्षम है और वह आधुनिक भी नहीं है। इस कर प्रशासन में इतनी क्षमता नहीं कि यह कर वसूली में वृद्धि कर सके। टैक्स आधार को मजबूत बनाने की बात कही गई है और उसके दायरे में और-और लोगों को लाने की बात कही गई है। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि टैक्स आधार व्यापक किया जाना और उसके दायरे में उन लोगों को लाना जो अभी तक टैक्स नहीं देते यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारा कर प्रशासन तंत्र मजबूत नहीं होता और कर प्रशासन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट बात हमको बजट में दिखाई नहीं पड़ती है। कंप्लायंस कल्चर मिसिंग है। इसका मुकाबला कैसे होगा और जो रियायतें दी गई है उनसे होने वाला घाटा अनुमान से ज्यादा हो सकता है। उसकी क्षतिपूर्ति का कोई भी एक स्पष्ट चित्र इस बजट से नहीं उभरता। वित्त मंत्री ने वालंटरी डिस्कलोज़र स्कीम की घोषणा की है। इससे कितनी वसूली हो पाएगी। क्या जितनी उम्मीद वह करते हैं वह पूरी होगी? पुरा अनुभव कोई सिद्ध नहीं करता। पहले भी इस प्रकार की मुआफी की स्कीमें घोषित की जाती रही हैं। लेकिन उनसे वसूली नाममात्र की हुई है। आपात्काल में एक मुआफी स्कीम घोषित की गई थी जिससे महज 246 करोड़ रुपया प्राप्त हो सका। इसी प्रकार 1985—87 की आम मुआफी स्कीम से महज 2500 करोड़ रुपये की वसूली हुई। 1991 में चालू की गई स्पेशल बेयर बांड स्कीम से महज 964 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इस तरह इन सब स्कीमों से जो कुल प्राप्ति हुई वह सिर्फ 4300 करोड़ रुपये की हुई। तो अब वित्त मंत्री कैसे कल्पना करते हैं कि वालंटरी डिस्कलोज़र स्कीम छप्पर फाड़ कर धन की वसूली कर देगी। यह स्कीम नैतिक दृष्टि से भी आपत्तिजनक है। इससे कर वंचन को प्रोत्साहन मिलेगा। इमानदार करदाता हतोत्साहित होगा। सफेद धन वाला भी 30 प्रतिशत कर दे और कालाधन वाला भी 30 प्रतिशत कर दे। इससे मेहनत करके सफेद धन कमाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया

जाएगा। होना तो यह चाहिए था कि वित्त मंत्री कालेधन के सृजन को रोकने का कोई पक्का उपाय करते। लेकिन कालेधन के सृजन को रोकने की चुनौती का किसी भी प्रकार का कोई उपाय इस बजट में दिखाई नहीं पड़ता। करों की चोरी को रोकथाम कैसे की जाएगी, बकाया कर वसूली कैसे हो सकेगी? उपसभाध्यक्ष महोदय, मौजूदा कर प्रशासन-तंत्र इतना अक्षम है कि उस से यह उम्मीद नहीं की जा सकती।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उन्होंने पिछले बजट में जो वायदे किए थे, उन में से एक-दो वायदों को छोड़कर बाकी सारे वायदे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो वायदे पूरे नहीं किए वह महत्वपूर्ण वायदे हैं। उन्होंने यह कहा था कि एक्सपेंडीचर मैनेजमेंट एंड रिफार्म्स कमीशन का गठन करेंगे। वह इस का गठन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि सब्सिडी पर खुली चर्चा और बहस होगी और इस के लिए मैं एक डिस्कसन पेपर संसद में रखूंगा लेकिन वह नहीं रख पाए। महोदय, 1996-97 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में सब्सिडीज 16,694 करोड़ थीं और 1997-98 के बजट एस्टीमेट में यह सब्सिडीज बढ़ाकर 18291 करोड़ कर दी गयी हैं। इन सब्सिडीज का क्या परिणाम हमारी अर्थ-व्यवस्था पर हो रहा है? सब्सिडीज को बढ़ाए जाने की कितना तर्क बनता है या नहीं बनता, इस पर खुली बहस की आवश्यकता है और वित्त मंत्री जी ने सब्सिडीज पर जो चर्चा-पत्र या डिस्कसन पेपर संसद में रखने का वायदा किया था, उस को पूरा करने में वह असफल हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बजट मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। यह मुद्रास्फीति पहले ही लगभग दोगुनी होकर 8 प्रतिशत तक पहुंच गयी है और यह बढ़कर 2 अंकों में प्रवेश करने वाली है। अब इस मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना और उस के कारण और आधार क्या हैं? रेल माल-भाड़े में 12 प्रतिशत. की वृद्धि की गयी है। क्या यह मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाएगी? पेट्रोलियन पदार्थों की कीमतों में वृद्धि अनिवार्य हो गयी है और 18 हजार करोड़ रुपए का तेल पूल खाते का घाटा हो गया है और आने वाले किसी भी समय में जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की जाएगी तो क्या उस से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी? संशोधित सार्वजनिक वितरण योजना यानी रिवैम्प्ड पी०डी०एस० के लिए अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी की व्यवयस्था करनी होगी। क्या उस से मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी? पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 11,325 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ेगा। क्या इस से मुद्रास्फीति नहीं होगी? महोदय, 16 हजार करोड़ का मोनेटाइज्ड घाटा बजट में रखा गया है। क्या इस से मुद्रास्फीति नहीं होगी? सर्विस टैक्स से 1200 करोड़ रुपए का बोझ आम आदमी पर लादा गया है। पोस्टल दरों से 300 करोड़ रुपए का बोझ आम आदमी पर लादा गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाय रोड के कारण माल ढुलाई में वृद्धि होगी और इन सब चीजों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी जिस का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। आम आदमी जिस की मार को सहता है, उस बढ़ने जा रही मुद्रास्फीति को रोकने का कोई उपाय इस बजट में नहीं किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने केन्द्रीय योजना व्ययमें कमी की है। अगर केन्द्रीय योजना व्यय में कमी होगी तो विकास की गति रुकेगी। वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय योजना व्यय 87,086 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन उस में कटौती कर के 1996-97 के संशोधित अनुमानों में 77,518 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह करीब 10 हजार करोड़ रुपए की यह कटौती कर दी गई है जोकि 11 परसेंट की कटौती है और मुद्रास्फीति की 8 प्रतिशत दर इस में जोड़ दें तो केन्द्रीय योजना व्यय में 19 प्रतिशत की कटौती की गयी है। महोदय, अगर केन्द्रीय योजना व्यय में 19 प्रतिशत की कटौती होती है तो उस का विकास पर कितना गहरा कुप्रभाव होगा, हानिकर परिणाम होगा, इस की कल्पना हम कर सकते हैं और उपसभाध्यक्ष महोदय, कटौतियां किस-किस क्षेत्र में की गयी हैं? महोदय, ये कटौतियां महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की गयी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बजट एस्टीमेट में 13,526 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया था जिसे घटाकर रिवाइज्ड एस्टीमेट में 11,403 करोड़ कर दिया गया है। पावर के क्षेत्र में 6790 करोड़ रुपया रखा गया था जिसे घटाकर 5661 करोड़ कर दिया गया है। रूरल डवलपमेंट जिसकी बहुत दुहाई दी जाती है, उस के लिए 2195 करोड़ का प्रावधान किया गया था और घटाकर 1798 करोड़ कर दिया गया है।

रूरल एम्पलायमेंट एण्ड पावरटी एलीविशन में 6,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था बजट एस्टीमेंट में, लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में उसको घटाकर 5977 करोड़ कर दिया गया। वाटर रिसोर्सेज में, एटामिक एनर्जी में , शिक्षा में 24 प्रतिशत की कटौती कर दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में 19.2 प्रतिशत की कटौती कर दी गई। कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में 13

प्रतिशत की कटौती कर दी गई। लघु उद्योग और कृषि आधारित उद्योग, उसके लिए 607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में उसको घटाकर 443 करोड़ कर दिया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस तरह से वित्त मंत्री महोदय ने अपने प्रथम बजट भाषण में जो यह दावा किया था कि वह केन्द्रीय योजना परिव्यय में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, उनकी यह घोषणा, उनका यह दावा बिल्कुल मिथ्या सिद्ध हुआ है और यह वृद्धि मात्र 3.9 प्रतिशत हुई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी फिसकल डेफिसिट की चर्चा आई। फिसकल डेफिसिट को कम करके दिखाने के लिए कैसी अजीब किस्म की कसरत वित्तमंत्री जी को करनी पड़ी है कि पहले कटौतियां कर दीजिए, योजना व्यय को फ्लेश-डाउन कर दीजिए और फिर कहिए कि देखिए, हमने फिसकल डेफिसिट कम करके दिखा दी है। जैसे गए वर्ष में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो राशि रखी गई थी वह राशि खर्च नहीं हुई और कहा गया कि फिसकल डेफिसिट कम हो गया। इस प्रकार से फिसकल डेफिसिट को कृत्रिम तरीकों, से बनावटी तरीकों से कम करके दिखाने से देश के अंदर विकास नहीं होगा और न गरीबों का फायदा होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश कर्ज के फंदे में फंस गया है और वित्तमंत्री जी का यह बजट इस कर्ज के फंदे-से मुक्ति का कोई सुझाव नहीं सुझाता। व्याज अदायगी की रकम में तेजी से वृद्धि हो रही है। आप जरा देखिएगा, कि वर्ष 1996-97 में ब्याज अदायगी 58,500 करोड़ रुपए रखी गई और यह सकल राजकोषीय घाटा, ग्रोस फिसकल डेफिसिट जो है 63,131 करोड़ था, यानि 92 परसेंट ब्याज अदायगी हुई वर्ष 1997-98 में ब्याज अदायगी की रकम 68,000 करोड़ रुपए रखी गई है और ग्रोस फिसकल डेफिसिट 65,454 करोड़ है, यानि 103.8 परसेंट। ऐसे जो हम कमाते है, उसका 27 परसेंट ऋण ब्याज के रूप में चला जाता है। सरकारी देनदारियों में अपूर्व वृद्धि हुई है। सरकारी कर्ज का बोझ वर्ष 1996-97 में 6,68,519 करोड़ हो गया। इसको हम कैसे कम कर पाएंगे? घरेलू बचत बढ़ाने को प्राथमिकता दिए बिना और कोई रास्ता नहीं है। सरकार का तो ऐसा है कि अंधाधुंध कर्ज लिए जाओ देश के भीतर से ओर देश के बाहर से, फिर ब्याज अदा किए जाओ। जितना हमारा फिसकल डेफिसिट, उससे कहीं ज्यादा हमारी ब्याज अदायगियां। यह कर्ज के फंदे में फंसना नहीं है तो फिर कर्ज के फंदे में फंसना किसे कहते हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है डिफेन्स का, रक्षा का, लेकिन रक्षा के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? 35,620 करोड़ रुपए का। अब ऊपर से देखने पर लगता है कि रक्षा बजट में कुछ वृद्धि की गई है यानि 16.1 प्रतिशत के स्थान पर 17.1 प्रतिशत हुई। लेकिन, यह वृद्धि तो पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए जो 3260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसके कारण है। अगर इसको हटा दिया जाए तो रक्षा बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त वृद्धि न करना चिंता का कारण है। रक्षा पर खर्च बढ़ाए जाने का एक जस्टिफिकेशन कैसे बनता है? उसको अनदेखा किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आयात शुल्कों में कमी कर दी गई है। कोई बात नहीं, लेकिन किसी ठोक आयात नीति की पृष्ठभूमि में आयात शुल्कों में कमी की जाती तो बात कुछ समझ में आती। वित्त मंत्री जी ने तो बगैर ठोस आयात नीति के आयात शुल्क घटा दिया है। इसका स्वदेशी निर्माताओं पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय.....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): कोहली साहब, जरा समय का भी ध्यान रखें।

श्री ओ०पी० कोहली: मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष, मैं कह रहा था कि देश के आर्थिक विकास का आधार है बुनियादी ढांचा क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर। लेकिन इस इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर की एक अरसे से अनदेखी होती रही है और मौजूदा बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने इसकी अनदेखी की है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए हमें जितनी बड़ी मात्रा में धन चाहिए। उस धन की व्यवस्था इस बजट में नहीं है। फिर बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? तो उम्मीद की गई है कि निजी क्षेत्र के सहारे इसका विकास कर लिया जाएगा और निजी क्षेत्र में घरेलू निजी क्षेत्र और विदेशी निजी क्षेत्र के सहारे वित्त मंत्री ने उम्मीद की है कि बहुत बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र पैसा बरसा देगा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास हो जाएगा, लेकिन अनुभव से यह बात सिद्ध नहीं हो रही है और जब तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास नहीं होता, तब तक विकास का जो भी

महल वित्त मंत्री जी ने खड़ा किया है, वह केवल सपनों का महल होकर रह जाएगा।

बिजली का क्षेत्र हो, कच्चे तेल का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में विकास के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। 40 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की जरूरत आने वाले पांच वर्षों में पड़ेगी। इसके लिए जितना धन चाहिए होगा, कहां से आएगा? सार्वजनिक क्षेत्र उसको जुटा पाने में असमर्थ है, तो क्या विदेशों से आएगा, क्या निजी क्षेत्र देगा? अब तक उनका रिस्पांस क्या रहा है? इन सब बातों को देखने से लगता है कि वित्त मंत्री जी का आशावाद मिथ्या आशावाद है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक और ग्रामीण विकास का क्षेत्र है। संयुक्त मोर्चा सरकार अपने कॉमन मिनिमम् प्रोग्राम में गरीबों की दुहाई देती है, सामाजिक न्याय की दुहाई देती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास की अनदेखी इस बजट में की गई है। सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए जितना पैसा रखा जाता है, वह खर्च नहीं होता। अंडर स्पेंडिंग, अंडर यूटिलाइजेशन आफ ऐलोटिड फंड्स यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। आप देखिए कि 1996-97 के बजट ऐस्टीमेट में जो राशि प्रोजाइड की गई सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए, 1996-97 के रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में उसमें भारी कटौती कर दी गई शिक्षा के क्षेत्र में कटौती की गई, ग्रामीण के क्षेत्र में कटौती की गई शिक्षा के क्षेत्र में 3,388 करोड़ की राशि को कम करके 2,574 करोड़ कर दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण विकास की राशि को 2,195 करोड़ से कम करके 1,798 करोड़ कर दिया गया। ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी निवारण के लिए राशि को 6,437 करोड़ से कम करके 5,577 करोड़ कर दिया गया और कृषि तथा सहकारिता क्षेत्र के लिए 1,471 करोड़ की राशि को कम करके 1,388 करोड़ कर दिया गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, सामाजिक क्षेत्र के लिए 1996-97 के बजट ऐस्टीमेट में 20,324 करोड़ रुपए रखे गए थे, 1996-97 के रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में इसको घटाकर 18,805 करोड़ रुपए कर दिया गया। इससे सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास को वित्त मंत्री ने अपने बजट में अहमियत नहीं दी है, यह नतीजा निकलता है। ग्रामीण रोजगार और विकास योजनाओं के लिए बजट राशि डेढ़ प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत के बीच में रही है। राज्य सरकारें अपने हिस्से का पैसा देती नहीं है और सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के जितने भी प्रकल्प और कार्यक्रम हैं वे ग्राऊंड लेवल पर कार्यान्वित नहीं होते क्योंकि कार्यान्वियन और मॉनिटरिंग का तंत्र बहुत कमजोर है. बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। इसलिए इस क्षेत्र की योजनाओं के पुनर्निरीक्षण की जरूरत है। दावे तो बड़े-बड़े किए गए हैं लेकिन वे दावे खोखले हैं, गरीबों तक इन कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, रोजगार के क्षेत्र का अगर विचार करें तो एक कल्पना की गई थी, दावा किया गया था कि प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस सपने का क्या हुआ क्या 10 मिलियन रोजगार के अवसर प्रतिवर्ष सृजित हो रहे हैं? कृषि में सार्वजनिक विनियोग में कमी आई है और कृषि रोजगार देती है। जब कृषि में सार्वजनिक विनियोग में कमी आई है तो कृषि के रोजगार सृजन करने की क्षमता में भी कमी आई है। कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। लघु उद्योग रोज़गार पैदा करते हैं लेकिन लघु उद्योगों में मंदी आई है। महोदय, कृषि और लघु उद्योग जो रोजगार सृजन के सबसे बड़े क्षेत्र हैं, जब उनमें गिरावट आई है, उनमें मंदी आई है तो फिर भला रोज़गार के विषय में जो एक लक्ष्य रखा गया था 10 मिलियन रोज़गार पैदा करने का, वह कैसे पैदा हो सकता है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि विकास की बात देखें तो यदि ईश्वर की कृपा होती है, मानसून अच्छा होता है तो कृषि विकसित होती है। आसमान पर कृषि निर्भर है, हमारे अपने प्रयासों और प्रयत्नों पर नहीं। यह तो ईश्वरीय कृपा है कि पिछले अनेक वर्षों से लगातार अच्छा मानसून आता रहा है। भगवान न करे अगर कभी मानसून बिगड़ जाए, मानसून की कृपा न हो तो हमारी कृषि की क्या हालत होगी? महोदय, सार्वजनिक विनियोग कृषि के क्षेत्र में घटा है। जहां 1996-97 के बजट ऐस्टीमेट्स में कृषि के लिए 11,599 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, इस साल उसे कम करके 10,099 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी इसमें 13 परसेंट की कमी की गई है। महोदय, 1996-97 में अन्न उत्पादन में 3.15 मिलियन टन की कमी हुई। खाद्य तेलों की आवश्यकता और उपलब्धि में 940 मिलियन टन का अंतर है। ऐसी स्थिति में कृषि जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके लिए जो उचित व्यवस्था करने की जरूरत थी, वह नहीं की गई।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में स्वर्ण क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का जिक्र किया था, उसको मैं स्पर्श नहीं करूंगा। लघु उद्योगों के क्षेत्र में वित्त मंत्री जी ने 14 वस्तुओं को डि-रिज़र्व कर दिया है। अब जिन 14 वस्तुओं को इन्होंने डि-रिज़र्व किया है उनमें बिस्कुट और आईसक्रीम भी है। इन वस्तुओं को लघु उद्योग के दायरे

से बाहर ले आने की सोच क्या है, तर्क क्या है, इसको वित्त मंत्री ही जानें।

महोदय, जहां तक सार्वजनिक उपक्रमों का सवाल है, बजट में यह कहा गया था कि इंटर्नल ऐंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक ऐंटरप्राइजेज, इनसे हम 1996-97 में 54,373 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे लेकिन व्यवस्था कितने की हुई, मात्र 47,414 करोड़ रुपए की। यानी लक्ष्य 6,959 करोड़ रुपए, करीब 7 हजार करोड़ रुपए कल्पना से नीचे रह गया। यह स्वयं इस बात को परिलक्षित करता है कि सार्वजनिक उपक्रमों की जो क्षमता है रिसोर्सेज जनरेट करने की, वह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। महोदय, 241 सार्वजनिक उद्योगों में से 104 सार्वजनिक उद्योग घाटे में चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों से इंटर्नल और ऐक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कैसे जनरेट होंगे? अभी वित्त मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि 1997-98 के बजट में हम 55,709 करोड़ रुपए यहां से प्राप्त कर लेंगे लेकिन पुराने अनुभव इसको सही सिद्ध नहीं करते।

महोदय, उत्पादन में सर्वतोमुखी कमी दिखाई पड़ती है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट हुई। बिजली उत्पादन में गिरावट हुई। कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट हुई। निर्यात वृद्धि की दर में गिरावट हुई। कृषि उत्पादन में गिरावट हुई। सार्वजनिक उपक्रमों की रिसोर्सेज जनरेट करने की कैपेसिटी में गिरावट हुई। यह दृश्य हमारे सामने है और इस दृश्य के होते हुए वित्त मंत्री जी न तो सरकारी खर्चों में कमी का कोई एक स्पष्ट चित्र और योजना लेकर सामने आए हैं, न ही गरीब तबके को इस बजट से कैसे राहत मिलेगी, इसका कोई चित्र लेकर सामने आए हैं। केवल एक आशावाद पर उनका सारा का सारा बजट टिका हुआ है और वह आशावाद यह है कि कुछ संपन्न वर्गों को रिआयतें दे दो, वह चुप कर जाएगा, विरोध नहीं करेगा, बोलेगा नहीं और यदि यह वर्ग संतुष्ट रहा तो फिर गरीबों की उपेक्षा होती है तो होती रहे, पिछड़ों की उपेक्षा होती है तो होती रहे। यह पूरा का पूरा बजट सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध पड़ता है। जो दावा किया गया है कि यह बजट ग्रोथ ओरियेंटेड है, मैं कहता हूं कि यह ग्रोथ ओरियेंटेड माईनस सोशल जस्टिस, माईनस इक्विटी है। इसलिए इस बजट से गरीब को कोई राहत नहीं मिल रही है। यही कारण है कि आज इस बजट की वाह-वाह कौन कर रहा है—समाज का वोकल वर्ग, संपन्न वर्ग, जो निवेश करना चाहता है। विदेशी निवेशक हों, देशी निवेशक हों, उद्योगपति हों, कारपोरेट सैक्टर हो यह तो इस बजट की वाह-वाही कर रहे हैं लेकिन आम व्यक्ति को लगता है कि इस बजट से मेरा क्या लेना-देना, इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, भाग्य कहां बदलने वाला है, इससे मुझे क्या राहत मिलेगी, शिक्षा की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, स्वास्थ की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। इसलिए आम व्यक्ति को इसमें कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ती और यही कारण है कि आम व्यक्ति की इस बजट में न कोई रुचि है, वह बिल्कुल उदासीन बैठा है, उसका इस बजट से कोई सरोकार नहीं है और हमारे वित्त मंत्री जी यह जो कारपोरेट सैक्टर, यह जो निवेशक, यह जो विदेश निवेशक, यह जो देशी निवेशक हैं, यह जो सम्पन्न वर्ग हैं इनकी वाह-वाही से फूले नहीं समा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक राह पर लाने में और ठीक दिशा देने में वित्त मंत्री का यह बजट कोई भूमिका नहीं निभाता। इसमें आशा की किरण नहीं छोड़ी, निराश ही अधिक किया है। इसलिए मैं इस बजट के जो नकारात्मक पहलू आम आदमी को अनुभव होते हैं उसको वाणी देने के लिए, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ था। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Shri R. K. Kumar, please. Before Mr. Kumar starts, if I have the sense of the House, if the House agrees, I would request Shrimati Chandra Kala Pandey to take the Chair for some time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY) in the chair.

SHRI R. K. KUMAR (Tamil Nadu): Madam, maiden Vice-Chairperson, ...

SHRI T. R. BAALU: Maiden?

SHRI R. K. KUMAR: For the first time she is occupying the Chair. Therefore, I said: 'Madam, maiden Vice-Chairperson'.

Madam, I rise to speak on the Budget for 1997-98, on behalf of the AIADMK Party. Last year, the Budget speech of the Finance Minister ended with a *sher* from Iqbal. The *sher* was:

"चले चलिए कि चलना भी तो दलील कामरानी है,
जो थक कर बैठ जाते है वह मंजिल न पा सकें।"
जो थक कर बैठ जाते है वह ही नहीं जो डर कर बैठ जाते है वह भी मंजिल पा नहीं सकते है।

That was the first Budget of Mr. Chidambaram. He was afraid at that time. In many areas, he was not bold enough.

This year, however, he has not only been bold enough, but audaciously bold enough, I would say. He has been audaciously bold enough in bringing forward certain proposals.

The Budget has been receiving both boquets and brickbats. The bouquets are *from the IMF chief to the Indian captains* of industry; from Bill Gates to businessmen; from even persons like Harshad Mehta I would emphasise that. What are the euphoric expressions used? 'The Budget is bold'. 'The Budget is bold and beautiful'. 'It is innovative'. 'It is historic' 'It is epoch-making'. So much so, the Finance Minister is on record as having said: 'I was happy with the reactions; but I never expected this kind of euphoria'.

Now, what are the brickbats? These are: 'It is a *chettiar* Budget'. 'It is only for the rich people'. 'It is concerned only with the corporate sector'. 'It has no concern for the common man'. 'It is a prorich Budget'. This has been said by a CPI(M) Politburo member. One gentleman has even called it a 'conman's Budget'.

Madam, having given both kinds of reactions, I now want to say what kind of a Budget is this. We have a saying in Tamil:

Koorai yeri kozhi Pidika Madiyathavar vaanathai Keeri Vaikuhthan Poga Muyanranam

I will translate it into Hindi. It means: जो आदमी अपनी छत पर चढ़कर मुर्गी नहीं पकड़ सकता वह आकाश में दौड़कर स्वर्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है।

I will explain why I feel this way. I feel this way because these estimates have been audaciously bold. Of course, I agree. You have to fix the targets at a slightly impossible level. Then only you can reach, at least, somewhere. If you keep the target itself very low, you will reach nowhere. But I have a very lurking fear about this Budget. I may be corrected. This budget is the result of balancing act. How has it been done? I will explain it to you. I take a loan from a bank. I have to repay it over some number of years. Every year some principal and some interest have to be paid. A company's net profit after tax but before depreciation should be 1.8 times the principal instalment plus interest. That is the debt service coverage ratio. Normally these projections are given, we calculate backwards. It was a pencil and erasor job earlier. But now it is a computer command job. I work out what should this be. What should be my net profit after tax but before depreciation? If I arrive at a profit, what should be my sale, and what should be the cost of sale? So, I find justification for all that.

This Budget has also been made in the same way. You fix this. The deficit should be 4.5 per cent of the GDP. I assume 7 per cent growth in the GDP. I know what would be 4.5 per cent of the GDP. After arriving at that, you proceed further. To reach this deficit, what should I do? There should be 15 per cent enhancement in the collection of revenue. We have no control over the expenditure. The expenditure remains as it is. As far as direct tax is concerned, we assume that lowering of tax-rates will bring additional revenue.

Madam, I want to point out that nobody pays tax without a plan. These days everybody, an individual or a corporate body, has a tax plan. I pay whatever tax I want. I always correlate my income to my spending and investment. Then, I arrive at my income and the tax I have to pay.

Again, my experience is this. It is claimed that lowering of the tax-rate will

bring in additional revenue. Maybe, they have some basis for that. But my experience is this. Hongkong is the country with the least tax. The maximum rate of tax is 15 per cent. Who maintains double accounts there? Only the Indian business community maintains double accounts there. Why? That is the psychology.

I pay sales-tax. I see some goods. I see something tangible. I pay the road-tax. There are roads. I pay the municipal tax. There is sewerage. There are street lights. I get something. But only about the income-tax, I do not see anything. I do not see any tangible benefit. Leave alone tangible benefits. You cannot give them. There is no distinction between a tax-payer and a non-taxpayer. How do you induce people? How do you motivate people? Merely by lowering the tax-rate, I am sorry, I am afraid it is not going to enhance the revenue collection. This is as regards the direct taxes.

As regards the customs duty, it is assumed that by lowering the customs duty, there will be 15 per cent increase in the revenue. I read a report that to be able to do that, there should be Rs. 40,000 crores worth of additional imports. Is it possible? It is a very big question.

[The Vice-Chairman (Shri Triloki Nath Chaturvedi): In the Chair]

The growth of the GDP for the last three years has been steadily at around 7 per cent. With 7 per cent growth in the GDP, have you seen any spurt in demand for goods and services in the last three years? If it was so, when you anticipate only 7 per cent growth in the GDP in the next year also, wherefrom is a higher demand for services and goods going to come suddenly? How are we going to get more Central Excise duty without a spurt in the demand? This is also another big question.

Madam, having said that, ...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam has gone. Sir has come now.

SHRI R. K. KUMAR. So sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): There was a sudden transformation.

SHRI R. K. KUMAR: I apologise. *...(Interruptions)...*

Nothing has been done for reduction of the expenditure. We are only assuming that the revenue will be more. We are not concentrating on reducing the expenditure. I have to give credit to the finance Minister that he has openly admitted that even the very first step that he promised last year of constituing an Expenditure Management Commission is still to see the light of the day.

Sir, there is a fiscal deficit of 4.5 per cent. As I told you earlier, we do this balancing thing. How do even the nationalised banks publish their balance-sheet? They do the balancing act. The amount of dividend that they have to give to the Government is fixed. Then on your interest receipts and interest payments, you cannot do anything. On expenditure side, you cannot do anything. So in between, the balancing figure is provisioning. For that you have doubtful debts. Earlier they used to haggle with the auditor and reduce the provision to arrive at the income-tax provision and then dividend. After the IRAL norms have come in, we have seen a lot of banks going in, red. Here in this Budget I find borrowing as the balancing figure and it is at Rs. 65,000 crores. As against the borrowing of Rs. 65,000 crores, the interest payment amount is Rs. 68,000 crores. We are going to borrow to pay interst. The whole House has been concerned with unincorporated bodies in Tamil Nadu with lot of finance companies taking deposits and cheating people. Now, when the Government of India borrows money to pay interest, I can say that the Government of India is also becoming an unincorporated non-banking finance company.

Now, Sir, what is the oil pool deficit? The hon. Petroleum Minister is here. If I am wrong he can correct me. The oil

pool deficit represents the money owed by the Government of India to the oil companies. Now, how do the oil companies manage? Well, they pay the customs duty, the excise duty etc., and to pay money to the Government they borrow. Wherefrom do they borrow? They borrow from the I.D.B.I. and other financial institutions. If this money is not paid to them, to that extent the liability of the Government of India is understated. How long can they go on like this? Though they may say it is outside the Budgetary exercise, in reality the oil pool deficit represents the liability of the Government of India. Earlier, before the Budget, administered prices used to be increased and it was said that the increase would cover the deficit. But, this year nothing has been done and we do not know what is going to be done.

SHRI T. R. BAALU: So, you are surprised, because it has not been increased.

SHRI R. K. KUMAR: My point is, if you had increased it already, then non-provision in the Budget could be justified. You have not increased the administered prices earlier to the Budget, because the Government does not want to become un-popular. We know the deficit. If you had already increased it, you would have become unpopular. By not increasing it, you are not providing for the liability of the Government. So, the whole Budget exercise is like banks balancing their balance-sheet to declare dividend to the Government or the companies obtaining loans, giving the D.C.S.R. as per bank norms. My charge is that this Budget has been balancing act. It is not based on reality. That is my lurking fear. If the exercise had been done in that manner, we are going to be in a very serious problem within three to six months. Sir, since my party has only half-an-hour and two Members of my Party want to speak, I, being the Deputy Leader of my Party, will accommodate them. So, I will take only five minutes more and go direct to the direct tax proposals.

Sir, much has been said about lowering of the direct taxes. They have reduced the tax from 15, 30 and 40 pert cent to 10, 20 and 30 per cent. Sir, a figure has been given saying that only 12 thousand people file tax returns of more than Rs. 10 lakh. We do not know how many people pay tax on income up to Rs.1 lakh. By lowering the tax, how much money are you going to get? The Finance Minister says, "I am putting so much of money in the hands of the tax-payers." They will spend or save. Well, what do they save? Up to Rs. 1 lakh, Rs.5,000. How many assessees are there? Twelve thousand assessees have income of Rs.10 lakhs. I take it as fifty times of that as people having Rs.1 lakh income. Then also it will be only Rs. 300 crores. Is Rs. 300 crores going to do any magic? How can you say by lowering the tax, you are putting so much money in the hands of the tax-payers and that demand will be created? Either they will spend or save. That argument does not hold good.

Now, Sir, coming to the 'presumptive tax', no doubt the Rs.1,400 scheme has been abolished. A new provision instead has been introduced saying if you do not show an income of 5 per cent of your gross turn-over, those who have a turnover of less than Rs.40 lakhs, will have to keep books of account and get it audited.

6.00 P.M.

What I am saying is against my own profession. If this provision is there, my professional brothers, auditors would get a lot of work. But take the case of a small trader with Rs. 20 lakhs turnover. If he maintains his books, it is all right. If he doesn't show 8 per cent or 5 per cent or whatever it is, you scrutinise his return. Why do you want him to spend money and go to an auditor and get it audited? So, I request that the requirement of tax audit for small traders should be done away with.

Now, I want to draw your attention to a provision in the Finance Bill. Section 44 (b) shows an amendment with retrospective effect from 1976-77. It is not the scheme of the Income Tax Act. It is totally wrong. If some mistake has crept in, you have got four years limitation under section 154. You have got two years limitation for giving effect to appeal under section 153. If the income has escaped assessment due to concealment, the maximum period is 10 years. But here in this section 44 (b) it has been given with retrospective effect, from 1976-77, about 20 years. How is it possible? How can an assessment of 20 years old be reopened? This is for the Finance Minister to consider. In Section 44 (b) the Finance Minister says that the proposed amendment would take effect from a retrospective date, the 1st April, 1976, some 21 years back and would accordingly apply in relation to the assessment year, 1976-77 and subsequent years. Maybe a decision from the Supreme Court or a High Court has just come relating to that year and that is why he wants to give effect to it. He cannot make a legislation making it applicable from 20 years back. It is unthinkable of.

Sir, in the dividend tax an illusion has been created. Earlier section 22 was there in the Act of 1922. For non-declaration of dividend, there was 25 per cent additional tax. The same thing happened in section 104 of 1961 Act in respect of closely held company. If they did not declare dividend, we were levying on them 25 per cent tax. Now, we are levying 10 per cent tax on those companies who declare dividend. Sir there are a large number of companies, there are a large number of shareholders who get dividend and that dividend is also exempt under section 80 (L) up to Rs.13,000. What is going to happen is, these companies, who pay tax of 10 per cent, to that extent, they are definitely going to declare lesser dividend. This provision is not in the interest of small shareholders, but only in the interest of big shareholders.

Sir, corollary to this is the object of introduction of the MAT. Last year it was said that a lot of companies were declaring dividend without paying tax. When you introduced the MAT, there was a lot of opposition. You have brought is a cumbersome procedure of credit in the subsequent years. Now you tax 10 per cent on the dividend declared. These two, in my opinion, cannot go together. So, I suggest either you don't tax 10 per cent on the dividend declared or you completely withdraw the MAT. Don't go in for all cumbersome procedure of claiming credit in the subsequent years.

Sir, in the last Budget, I made a submission with regard to the simplification of procedure. When you file a tax return, and there is no question to be asked. They have to send an intimation for the assessee that it has been accepted. In many cases, the Income Tax Department doesn't do it. So, I advise all my clients to pay Rs.100 or Rs.200 less so that they will demand that and I will know that it has been completed.

I thank the hon. Finance Minister for introducing a provision under section 143 (1) (c). This is a provision under which intimation would be sent to all the assessees whose returns have been accepted. But my submission is that there is no time-limit. There should be a time-limit. Today if I file a return whether it is accepted or not, unless I pay the tax short by a llittle amount, it is not known. So, my submission is that within a particular time, the intimation should be given to the assessee.

Sir, I want to point out about the withdrawal of section 80 GG, that is, relief for house rent paid by those people who don't get house rent allowance. People getting house rent allowance already get the benefit under tax exemption. But those who don't get

house rent allowance, by withdrawal of section 80 GG, they stand to suffer. So, I suggest that section 80 GG should not be withdrawn.

Then, coming to the four criteria, already, a lot of people are transferring their cars, to the names of their wife or sons and telephones to somebody else's name. This is not the way you want to rope in or widen the tax net. As I said, there should be some recognition for the tax-payer. When I buy a new car, in Madras, I go for its registration. I am an income-tax payer. But the motor vehicles authority does not bother about all these things. He wants my ration card. I do not have a ration card because I am not eligible for it. Now, I find it difficult to register my vehicle. Why can't the motor vehicles authority ask for my income tax number or my Permanent Account Number? Instead of saying "you file the returns", it should be the other way round. The department is so corrupt that anything can be overcome. All these four criteria are not going to help the department in any way. But it can be done the other way round. When a person registers his car, the motor vehicles authority should ask for his income-tax number; when a person buys his airlines ticket for foreign trip the airlines company should ask for his income-tax number. That way, you can rope in a lot of people.

There is another important thing which affects me personally and a lot of professionals and that is the amendment to section 80(0). Earlier it covered fees received in foreign exchange by professionals also; there was 50 per cent exemption. Now it is restricted to patents, royalties and things like that. The hon. Minister was not a Minister for a brief period, after being the Commerce Minister. It was reported that he had given advice to Enron, etc. If he received the fees in foreign exchange, he was getting exemption. A lot of architects, advocates and chartered accountants render service to foreign companies and earn foreign exchange. The object of section 80(0) is to enhance foreign exchange earnings. There is abosolutely no justifcation for withdrawing this concession given to encourage earning foreign exchange. I strongly request the restoration of professional fees in section 80(0).

Then, there is no justification for the firm tax at 35 per cent. Earlier, the maximum rate was 40 per cent, whether individual or firm. Now, the rate for individuals has come down to 30 per cent. But, the firm tax is at 35 per cent. There is no justification for this. Again, they are liberalising everything; the artificial disallowance on guest house, entertainment etc are being withdrawn welcome it. But, what about the salary paid to partners? To that extent, there is double taxation. The firm pays tax and the partners also pay tax. At least there should not be a ceiling on this. The partners' salary, at least in repsect of professional firms, should not be disallowed. That provision should be amended. If it is not done, I would advise all the partners of firms to start as many guest houses as they want; to entertain as much as they want. By this, we are encouraging professionals and partners of business firms to be dishonest. Artificial disallowances are removed. But still, there is an artificial disallowance in repsect of salaries paid to partners.

Coming to central excise, I have two submissions to make. The hon. Finance Minister's proposal reads that all the re-rollers are the same. Somebody has done something wrong and the basis of taxation becomes the installed capacity. There is a saying in Tamil:

Kuthiraippu "Kurram" Yenral

Yanaippu "Arram" Agathu

If you call the horse 'kurram' in Telugu, then, the elephant cannot be called 'yerram'. If somebody has done

something wrong, why do you want to penalise all? There are genuine cases. There are genuine re-rolling mills who have problems, who cannot fully utilised the installed capacity. You cannot say all have to pay tax on the installed capacity. I am not manufacturing, I am sleeping; how can I pay tax on the installed capacity?

The second things is this. I may be wrong. I heard about it only yesterday. I had no time to check up. But the hon. Minister is here. I am told, now, after the Budget under a notification, tile factories, manufacturing roofing tiles, have to pay 15 per cent Central Excise, while the bricks are exempt from Central excise. This is an anomalous situation. As a matter of fact, when I started my practice I used to go from Madras to Mangalore, to audit and it a lot of tile factories.

You do not pay tax on the bricks used to build four walls. I am sure the Finance Minister does not want the poor people to live within the four walls, without a roof. This is an industry in the small-scale sector which is existing in Kerala and Mangalore. So, fifteen per cent Central Excise Duty on tiles is not justified at all. With these submission, I conclude my speech. Thank you very much.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity for offering my comments on the Budget that has been presented by the Finance Minister. I would like to compliment the Finance Minister on the Budget. I think this is a good Budget. The Budget had to address itself to outstanding economic problems, to gear up industrial production, to revive capital market, to promote exports, to assist the agricultural sector, to contain inflation and to provide funds for the social service sector. The Budget does all that. As per the report of the Lakdawala Committee, thirty-eight to forty per cent of the population of the country is still below the poverty line. I am glad that the Finance Minister has provided several measures to improve the lot of the poorest of the poor. Several schemes have been announced by him for strengthening various schemes which are already there, such as providing more funds for the Basic Minimum Service Plan, accelerated irrigation programme, the Ganga Kalyan Yojana, all these steps are steps in the right direction. I would like to make some suggestions. The Finance Minister has reduced taxes both at the personal level and at the corporate level. He has also abolished the dividend tax. But a new tax has been started which is to tax the distributor's profits of the company. The Finance Minister has said that this was to induce the companies which paid exorbitant dividends to retain profits. Now, the question is: How do you define the exorbitant dividends? What exactly do you mean by that? In my opinion this is another way of taxing the companies. Let us consider a practical proposal. Suppose a company has a net profit of Rs. one crore before providing for tax, out of Rs. one crore it has to pay Rs. 35 lakhs as tax. Then ultimately, the company is left with 65 lakhs. Suppose a company provides Rs. Forty lakhs as dividends which is not a high figure for a company earining one crore of rupees, and suppose a company were to provide 40 per cent, it would mean that the company will be required to pay an additional four per cent as corporate tax. Sir my suggestion to the Finance Minister would be that when he inflicts the charging company with heavy taxes, let there be at least some sort of understanding in his mind, some sort of assumption in his mind as to what he means by companies paying exorbitant dividends. I would suggest let 60 per cent of the profit be the limit. In case the company pays dividends up to 60 per cent of its profit it should not be required to pay any such tax. In case it pays over and above 60 per cent, then whatever be the amount of the additional dividend, the Finance Minister can certainly charge that company. Mr. R.K. Kumar has very intelligently analysed this

question. He said that as far as the shareholders are concerned, they would really welcome a decent increase in the dividend. Mr. Kumar, I am referring to you. You referred to the new tax of ten per cent.

So, in view of that, unless a case is built up against it, it will not be proper to charge taxes on dividends and I would recommend to the Finance Minister that he should reconsider this matter.

There is another important matter and that is about the overall additional revenue. The Finance Minister has taken it as 22,798 crores of rupees and this will look after the increase in expenditure. The success of the Budget really hinges on this single factor.

Sir, control of fiscal deficit is very important for the economy of the country. Our fiscal deficit pre-empts funds from the capital market. It raises the rate of interest. Higher fiscal deficit leads to higher inflation and lower growth. I am glad that the Finance Minister had, shomehow or the other, been able to contain the fiscal deficit to 5 per cent, for the year 1996-97. He is hopeful that in the current financial year he will be able to maintain it at 4.5 per cent, and he is targeting at 4 per cent for the next year. I am glad that this matter is receiving a great importance from the Finance Minister and I hope, he will succeed in his endeavours.

Then the Finance Minister has mentioned about three important measures to increase the competitiveness of the industry. Most of the markets will be introduced some of them shortly. One is buying back of shares by a company which is a system prevalent almost throughout the West. The second is modification of sections 370 and 372 of the Companies Act to provide greater flexibility to intercorporate investments. And the third is that FERA is to be replaced. FERA, in my opinion, should have been condemned by now. That could be replaced by Foreign Exchange Management Act. Sir, all these are steps in the right direction, and the sooner they are taken, the better for the people, the better for the corporate sector.

Sir, there is another good thing which the Finance Minister has done. As far as export earnings are concerned, they will no longer attract MAT. This is certainly a good thing. I only hope that the Finance Minister could completely abolish MAT. That would have been the best thing. But he has taken, at least, some measures. I would certainly compliment the Finance Minister on that, but, side by side, I would also like to remind him that it might not be a populist measure, and he will have to think over it as far as the value of the rupee is concerned. Sir, at present the rupee is quite strong, but as per the existing ordinary law of currency, in case in our country the inflation rate is 8 per cent and in the West it is 3 per cent, then it would mean that every year our products will become constlier by 5 per cent compared to foreign countries, and if that be so, even if foreign exchange comes into our country by FIIs, that would be no matter of satisfaction. The point is that despite all the decisions taken by him, they will not be able to compete wth others in the foreign markets. So, my suggestion to the Finance Minister is to think about this matter from time to time and in case he finds that our idigenous industries are not in a position to compete and that it is because of the higher inflaltion rates in our country, compared to other countries, he should give a second thought as far as the rupee value is concerned.

Sir, tariff rates are being reduced on a number of commodities. I perceive that this has become a kind of fashion that when we talk of globalisation and liberalisation, I think every Minister would like to show, well, how liberal we are and we would like to reduce the tariffs. Sir, it appears to me that in another six or seven years our customs duty will become 10 per cent. I don't

deny that it is in keeping with our commitment, our assurance to the WTO. As far as that is concerned, I have no quarrel. The question side by side is that indigenous industry should not suffer. I would like to mention that all the countries in the world including the most capitalist country of the world, the United States, look after their industry's interest and they make it sure that their industries, do not suffer. Therefore, I will plead with the Finance Minister, let him to go alongwith the WTO. But side by side let him liberalise the other protective laws. The anti-dumping law unlike other countries is presently taking enormous time to establish that dumping is taking place. I would like to mention that indigenous industries are prepared to face competition. Perhpas, you might have heard or you might have read in the newspapers that all we want is a level playing field. Some steps have already been suggested by the Finance Minister. I have thrown some light on them a few minutes back. There are three main deterrents which affect the competitiveness of Indian industry and they should be very carefully understood. One is the high rate of interest. Our rates of interest are 17% to 18%. In most of the countries of the west the rate of interest is 6% to 8%. At least in two countries, both are highly industrialised countries, Switzerland and Japan, the rate of interest is only 3% to 4%. How can our industries compete with others? We are charging an interest rate of 18% whereas other countries are charging an interest rate of 6% to 8%. Two important countries including Japan which is one of the top leaders of the world are charging interest at the rate of 3% to 4% only. I would suggest that as soon as possible our interest rate should be reduced at least by 4% to 5%.

Now take the case of power rates. What we are doing is...*(Interruptions)*

SHRI SATISH AGARWAL: Excuse me. How can the interest rates be brought down when the Government of India is borrowing at the rate of 13.85%?

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: That is a very important question which you have raised. It requires a long and detailed discussion. It cannot be done in this debate which is meant for a specific purpose. This is certainly a point on which I would like to have a discussion. I raised this question. The Indian industry is charged at the rate of 18%. It cannot compete with industries which are paying interest at the rate of 4% to 5%.

The other point is regarding power. What is happening? One section of the society is required to pay very low rate of power. That does not come out of the Budget of the Government. But another section of the society is required to finance that. The result is that our rates are three times higher compared to the rates prevalent in the western countries. Power rate plays a very important role because new machines are coming. With more and more modernisation power has become a very important factor and it plays a very important role, as far as cost of production is concerned. That apart, wherever power is supplied, in most of the States it is supplied by the State Electricity Boards. The supply of power is erratic. Every hour there is some breakdown or the other. it means, as far as sensitive machines are concerned, that if there are breakdowns in the sensitive machines and as a result the amount of repairs go up. This should receive the attention of the Government.

Now I come to a ticklish question. But it is a question which we should not fight shy of and he should try to face it. I will also suggest some measures to him. It is regarding the Exit Policy. Soon after the announcement of the Liberlisation Policy of the Government of India, it has been suggested from time to time that an Exit Policy is round the corner and it will be announced any day. But nothing has been done. All throughout the world, I would like to mention, the companies are

modernising. The companies are updating their plants. They are going in for most modern and updated technology.

What does modernisation mean? Modernisaton means more automation. Everyone is aware of the revolution which has taken place in the field of computers. Modernisation means more automation. More automation means more productivity and less labour. A question immediately arises: What will happen to the surplus labour? How will we absorb this labour? That labour has to be absorbed. They will not have to be paid idel wages. But that labour can be absorbed in other industries. As soon as the standard of a country improves it can absorb that labour. This is what is happening in all the Western countries. Once a company becomes more automated, it reduces its labour. But that labour is absorbed by some other industry. But the important thing is all these countries do not have 'Exit Policy'. This is a part of social security. If anyone is thrown out of the job, he gets some compensation which is enough for him to look after himself. The compensation is not given by the industry. It is given by the Government under social security scheme. The Government imposes some amount of taxes on all the people for this. When a factory reduces its labour, it is not required to pay any compensation. Unfortunately in our country, if we want to improve our efficiency by way of modernisation, by way of automation, it is absolutely impossible to get rid of labour. I don't say that they should implement the scheme today itself. But I would certainly say that they should start thinking on these lines just like they are thinking of globalisation. Social security is a thing which will be most welcome. I am sure the labour too will very much welcome it. It will also help our industries in getting more and more modernised.

Then something was mentioned about the Oil Pool deficit. One hon. Member even suggested that when you have got big reserves in the Oil Pool, i.e. Rs. 35,000 crores, why don't you debit the deficit there? I don't think that is the right answer. Even Dr. Manmohan Singh, who is a renowned economist and who was our Finance Minister till recently, stated that this was a matter into which we should go ahead. The only solution which appears to me is that we have got to raise the oil prices perhaps gradually. It may be a very unpopular decision. But this is the thing which has got to be done. I am sure the Finance Minister will do it, as the hon. Member has said, after the Session is over. In one of the post-Budget interviews the Finance Minister said that the Budget was not the right platform. That may be so. But the matter should not be delayed unnecessarily and unduely because this issue is linked with the fiscal deficit.

I would like to mention here that our oil production is unfortunately stagnant. In the year 1986 our oil production had reached 34 million tonnes. After that it has remained in this vicinity. But this year due to some peculiar circumstances our oil production would be only 30 to 31 million tonnes; hence there has been no improvement. Though the matter belongs to the Ministry of Petroleum, I would request the Finance Minister to talk to the Minister of Petroleum. What is the actual position? The position is that India is importing huge amount of oil. The amount involved is Rs. 22,000 crores. I would request the Finance Minister to take up the matter with the Ministry of Petroleum so that adequate amount is spent on locating new oilfields. Foreign oil giants should also be invited for exploring oil in India. Sir, something was said regarding infrastructure. My view is that due consideration has not been paid to it. If bottlenecks are not removed, our industries will suffer. What really bothers our foreign friends is our poor infrastructure. Our requirement of power alone is going to rise by 42,000 MW in the next five years. This will need an investment of about 50 billion dollors.

Then there are other items of infrastructure like ports, roads, telecommunications, etc., which will need another 50 billion dollors in the next five years. The total amount that we need to spend in the next five years is around 100 billion dollors or 20 billion dollors per year. This comes to Rs. 72,000 crores every year. It is a colossal amount. This can be only possible by the combined efforts of the Government of India, the Indian businessmen and foreign businessmen. The Voluntary Disclosure Scheme is a good scheme and it has got both good points as well as bad points. The Finance Minister has given an opportunity to people to disclose their hidden income. He has also granted amnesty from income-tax, wealth-tax and FERA. I would like to make a samll suggestion. Some traders of Delhi came to see me a few days ago. They said that during Indiraji's days too such a scheme was introduced. What happened was that, when these traders disclosed their income under this scheme, the sales tax people came after them. They said, "Since you have hidden income, you must have a higher turnover and that means, you have evaded sales tax". I know, sales tax is an item which is outside the purview of the Central Government. It is a State subject. But I would plead to the Government of India to at least, write letters to Chief Ministers asking them not to harass the traders. I wanted to express my views on the allocation made for Defence. The Finance Minister has made a solemn promise that additional requirement of defence capital expenditure will be met by him. He said that he will provide funds for that. Hence, I would not like to offer any comments on this. I only hope, the Defence Minister will fully examine it and in case there is a requirement, the same should be brought to the notice of the Finance Minister. Our capital market is in a poor shape. In the year, 1994-95, the total amount of money that was collected by the industry from the capital market was something like Rs. 45,000 crores. In 1995-96, it came down to Rs. 29,000 crores. In the current year, the collection has been only Rs. 20,000 crores. The Budget appears to be good. But the Finance Minister should keep a close track of it so that the money that we draw from the capital market goes up so that we are able to start new industries. Sir, I wanted to say something regarding searches and seizures.

Since. Mr. Salve has already made elaborate comments on it, I would only say that I fully associate myself with what the said. The Government of India should satisfy themselves fully that there is some evasion of tax before they carry out any search or seizure. They should not carry out such search and seizure operations on hearsay. I would like to make a mention about excise duty on molasses produced by the sugar factories. The sugar industry is passing through difficult times. Majority of the factories in India, particularly the factories in U.P. and Bihar have lost heavily this year. Now, Sir, this is an industry where lots of farmers are very much closely associated. Hundreds of crores of rupees at one time were outstanding to the farmers. Under those circumstances to tax this industry, in my opinion, is not proper. Then what is the amount of this tax which has been imposed? Formerly, the duty was only 20 per cent *ad-valorem*. The price of molasses was Rs. 100 to Rs. 200 per ton which means the amount of tax was Rs. 20 to Rs. 40 per ton. Now the excise duty has been raised to Rs. 500 per ton; an increase out of all proportions. I would only ask the Finance Minister to rethink as far as this matter is concerned because the sugar industry is really in a bad shape. Sir, I am coming to the end of my speech. I would say our aim should be 7 to 8 per cent rise in GDP, 4 to 5 per cent rise in agricultural production; 25 per cent should be our target for saving, there should be a rise of 25 per cent in exports and there should be a rise of 12-13 per cent in industrial production. Sir, I would suggest that these targets should always be reviewed by us and in case we

and anywhere some further modifications or corrections are required the same should be carried out. Sir, all the leading economists of the world and all the powers of the world, all the important powers of the world are saying that in about 10 years' time, two countries will emerge as new super powers. Sir, these are going to be China and India. I, Sir, have no doubt as far as this prophecy is concerned. I have not doubt in my mind that this prophecy will come true. I would only say that we have to work hard for that and we are going to work hard for the progress of the economy in all directions. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATRUVEDI): Shri Sanjay Dalmia. He is absent. Shri Sanjay Nirupam. He is absent. Dr. Mahesh Chandra Sharma.

डॉ० महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता नहीं था कि मेरे बोलने का नंबर आज आएगा इसलिए मैं अपने पेपर्स भी नहीं लाया हूं। फिर भी आपने बुलाया तो मैं बोलता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपका नाम इस सीरियल में है।

डॉ० महेश चन्द्र शर्मा: जी, मैं बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के जो अर्थशास्त्रीय प्रावधान है, उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और जो बातें कही गई है, वे भी नहीं दोहराना चाहता। मुझे इस बजट का जो वैचारिक और दार्शनिक पक्ष है, उसके बारे में कुछ कहना है। इस बजट पर जो नाम लिखा है वह तो श्री चिदम्बरम का है लेकिन मुझे लगता है कि यह भी श्री मनमोहन सिंह जी का ही बजट है। जिसको हमने लिब्रलाइजेशन या उदारवाद कहा है, इसकी धारा भारतवर्ष में प्रारंभ हुई और एकदम से समाजवाद से पूंजीवाद की ओर हमने छलांग लगा दी। यह बजट जिस अवधारणा पर गढ़ा गया है, उस अवधारणा के नायक हैं आर्थर डंकल।

जब से सोवियत रूस कोलेप्स हुआ है अमेरिका में एक ऐसा विचार प्रस्तावित हुआ है कि विचारधाराओं के संघर्ष के इतिहास का अंत हो गया है और अब जो गुट अमेरिका का है वही गुट विश्व का नायक बन गया है। उस विश्वनायक ने अपने आप को संसार पर आरोपित करने के लिए एक नारा दिया कि 'नाऊ वी मस्ट ग्लोबलाइज', अब हम अपने आप को भूमंडलीकृत करें। मान्यवर मैं अपने उन पूर्वजों को जो भारतवर्ष के लोकतंत्र के पुरोधा हैं, उनको नमन करता हूं। उन्होंने तब न तो पूंजीवादी गुट को स्वीकार किया और न समाजवादी गुट को स्वीकार किया और अपने आप को गुट निरपेक्ष कहा। लेकिन अब हमने, जो अपने आपको विजयी कहता है, उस गुट के सामने सरेंडर कर दिया है यह जो ग्लोबलाइजेशन है 'इट इज नथिंग बट इम्पीरियलिज्म', यह साम्राज्यवाद का एक नाम है। पश्चिमी अर्थ-आस्था में पैकेजिंग कुछ और होती है और कमोडिटी कुछ और होती है। जिसको पाश्चात्य लोग कम्पीटीशन कहते हैं। उसमें टाइटल है कंपीटीशन पर जक्स्टेन्ट है मोनोपलाइजेशन। विश्व बाजार में अपनी मोनोपली कैसे स्थापित की जाए, दुनिया के वह देश जो द्वितीय महायुद्ध के बाद आजाद हुए, इन्होंने आर्थिक स्वावलम्बन का नारा दिया और आर्थिक स्वावलम्बन के कारण जो पश्चिमी औद्योगिक क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति को वह बाजार नहीं मिला जिस बाजार की उसको भूख थी। मान्यवर, हमें मालूम है कि यह जो देश औद्योगिक क्रांति की बात आज दुनिया भर में कह रहे हैं, यह औद्योगिक क्रांति पश्चिम में कैसे हुई? यदि पश्चिम के देशों का उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एशिया में, अफ्रीका में और लेटिन अमेरिका में न होता तो वहां यह औद्योगिक क्रांति भी न होती। यह जो पूरा बजट है यह निवेश के आह्वण पर बनाया गया है, विदेशी निवेश चाहिए। मान्यवर, याद कीजिए कि जब हम समाजवाद को भगवान कह रहे थे तब हम कर्ज के इच्छुक थे और हम समझते थे कि हमारा आर्थिक स्वावलम्बन विदेशी कर्ज से आएगा। 40—45 साल की कर्जवादी अर्थ-व्यवस्था ने हमको कंगाल कर दिया और उसके बाद हम अचानक लिब्रलाइजेशन की बात कहकर दूसरे खेमे में चले गए। कल हमारा आर्थिक भगवान था कर्ज और आज हमारा आर्थिक भगवान हो गया है विदेशी निवेश। यह बजट इस बात का दस्तावेज है जो कल्पना आर्थर डंकल ने पश्चिमी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए की है, उसको विश्व बाजार चाहिए। और इसके लिए यदि उसको तृतीय विश्व का बाजार मिल जाए,—तृतीय विश्व के बाजार के अभाव में, तृतीय विश्व के प्राकृतिक साधनों के अभाव में पश्चिम की अर्थ-व्यवस्था कालेप्स कर जाएगी। तो, मान्यवर, यह दुख की बात है हमने अपनी खनिज सम्पदा को, हमने अपनी जल सम्पदा को विदेशियों के लिए खोल दिया है, यह दुर्भाग्य की बात है । जब से यह नारा लगा है लिब्रलाइजेशन का, आप मार्केट में

जाइए किसी भी जनरल स्टोर में हमें स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध नहीं होंगी। इस पांच साल की उदारी-व्यवस्था का यह परिणाम है कि हम अपनी उत्पादकीय संप्रभुता को क्रमशः खोते चले जा रहे हैं। मान्यवर, यह संभव ही नहीं है कि कोई देश अपनी उत्पादकीय संप्रभुता खो दे। यह संभव ही नहीं है कि कोई देश बाजार पर अपना नियंत्रण खो दे। बाजार की और उत्पादन की संप्रभता खोकर कोई देश राजनैतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी संप्रभू नहीं रह सकता।

इस बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों की ओर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। खाद्यान्न के क्षेत्र में ऐसा कहा गया है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और बढ़ा है। मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है। पर मैं सुनिश्चित हूं कि हमारे देश के आम आदमी की दालों की खपत घटी है। यह चमत्कार कैसे हो रहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, पर-कैपिटा खाद्यान्न अधिक पैदा हो रहा है लेकिन पर-कैपिटा कंजम्शन घट रहा है। पर-कैपिटा कंजम्शन घट रहा है इसकी ओर ध्यान न देना और बढ़ रहा है यही कहेंगे तो हम 'सरवाइवल आफ द फिटेस्ट' के अनुचर बन जाएंगे। हम केवल उनकी चिंता करेंगे जो अपने आपको फिट कहते हैं और हम जो अनफिट कहलाते हैं उनका मरना सुनिश्चित कर देंगे।

आजकल बड़ी बात चलती है जी०डी०पी० या जी०एन०पी० की। वास्तव में इस बात की जरूरत है कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसके आंकड़े देने के साथ ही यह भी बताया जाए कि यह सकल घरेलू उत्पाद हमने किस कीमत पर पाया है। हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज कितने खत्म किए, हमने कितनी वायु प्रदूषित की, कितने जल संसाधनों को नष्ट किया, कितने ऊर्जा संसाधनों को नष्ट किया। जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज थे उन बेसिक रिसोर्सेज के डिस्ट्रक्शन का आंकड़ा प्रस्तुत किए बिना एकांगी रूप से जी०डी०पी० का आंकड़ा देना एक प्रकार से भ्रमोत्पादक अर्थव्यवस्था की जगलरी में हमें ढकेलता है। यह पूरा बजट जगलरी ही है तथा कुछ बातें इसमें ऐसी ही हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी बातें बजट स्पीच में आनी भी चाहिए क्या। पश्चिम की एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। उसकी एक डिग्री को किसी वैज्ञानिक प्रतिभा के समकक्ष बताना, एक यूनिवर्सिटी का नाम इस प्रकार की स्पीच में आना चाहिए क्या?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि MBA graduate also pays tribute to a scientist.

डॉ० महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): हां, मुझे मालूम है। मुझे इस पर थोड़ी आपत्ति है। हो सकता है आपको ठीक न लगे। पर मुझे एक विश्वविद्यालय का नाम आना ठीक नहीं लगा। मुझे यह भी लगा कि यह पूरा बजट एक इस प्रकार के साहसिक तेवर को व्यक्त करता है जो अब यह कहता है कि घाटे के बजट की व्यवस्था और उसकी उद्घोषणा अप्रासंगिक हो गयी है। लेकिन साल के अंत में यही घाटा मौद्रिक घाटे के रूप में रिजर्व बैंक में अंकित हो जाएगा। यह 'बैक डोर' से घाटे को अंकित करने की क्या आवश्यकता है। यदि घाटे का बजट है तो हम साफ तौर से क्यों नहीं कह सकते हैं कि यह घाटा है और इसकी प्राप्ति की हमारी यह योजना है।

यह बजट जिनके द्वारा प्रशंसित हो रहा है, यह बजट जिस प्रकार से आ रहा है वह हमारे देश के एक और दुर्भाग्य को इंगित करता है और वह दुर्भाग्य यह है यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने वाला बजट है। आज भी इस देश में और इस सदन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिरफ्त में भारत का बाजार जाए इस बात को न मानने वालों का यहां बहुमत है सदन में उनका बहुमत है लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ है कि इस 'इक्रामिक इम्पीरिलिज्म' के खिलाफ जो लड़ाई करने वाले हैं वे कुछ दलों में इस प्रकार बट गए हैं कि उनकी सामूहिक आवाज आज सुनाई नहीं देती। आज जो लोग उधर बैठे है, वे सब वे लोग हैं जो गेट पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ थे। डब्ल्यू०टी०ओ० में भारत जिस प्रकार से गया, वे उसके खिलाफ थे। उस वक्त उदारवाद की बात चल रही थी। तब ऐसा लगता था कि हिन्दुस्तान की कोई भी विचारधारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा फैलाए जा रहे साम्राज्यवादी जाल के पक्ष में नहीं है। हिन्दुस्तान की मुख्यतया तीन विचाराधाराएं हैं। एक विचाराधारा जो आजादी के आन्दोलन से आई महात्मा गांधी की गांधीवादी विचाराधारा, दूसरी लैफ्ट की समाजवादी विचारधारा और तीसरी राष्ट्रवादियों की आर०एस०एस० बी०जे०पी० की विचारधारा। राष्ट्रवादी, गांधीवादी, वामपंथी अभी इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, कोई भी व्यक्ति इस 'सो-काल्ड ग्लोबलाइज़ेशन' के पक्ष में नहीं है। सभी ने इस के खिलाफ लेख लिखे, आन्दोलन किए, लोकिन यह सब होने के बावजूद स्थितियां ऐसी हैं कि हम को ग्लोबलाइज़ेशन के पीछे घिसट कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो कल तक विरोध कर रहे थे, जो आज

अखबार में और पत्रिकाओं में विरोध कर रहे हैं वे जब यहां देने लगेंगे तब पार्टियो में इस प्रकार बंट जायेंगे कि न गांधी की इच्छा पूरी होगी, न लोहिया की इच्छा पूरी होगी, न दीनदयाल उपाध्याय की इच्छा पूरी होगी, न जयप्रकाश नारायण की इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी जो गलोबलाइजेशन का मालिक है, जो पश्चिमी दुनिया का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक प्रकार से गुलाम बन गया है, इस प्रकार के राष्ट्र राज्यों के वलय की।

इसलिए मान्यवर, यह बजट तो छोटी चीज़ है। एक साल बाद फिर आ जाएगा उस में आंकड़े भी फिर-फिर दोहरा दिए जायेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1998-99 का बजट आएगा उस वक्त भारत के बाजार कितने स्वदेशी माल से आपूरित होंगे और कितने विदेशी माल से आपूरित होंगे? जब वह बजट आएगा तब भारतवर्ष के कितने स्वदेशी उद्योग दम तोड़ चुके होंगे? जब वह बजट आएगा तब भारतवर्ष के कितने लोग बेरोज़गार हो चुके होंगे? यह बिल्कल झूठी बात है कि इस प्रकार की आयोजन लोगों को रोज़गार दे सकती है। मान्यवर, यह बात छुपी हुई नहीं है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरो-अमेरिकी वर्ल्ड की पापुलेशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बिना जनसंख्या की वृद्धि हुए वहां बेरोज़गारों की वृद्धि हो रही है। उनके विकास के मॉडल को स्वीकार करके हम वे लाभ नहीं ले सकते जो लाभ वहां वे भी नहीं ले पाए और इसलिए इस प्रकार का आयोजन और इस प्रकार का बजट यह रोज़गारों का विध्वंस करने वाला है। यह बजट स्वदेशी माल को समाप्त करने वाला है, स्वदेशी कंपनियों का नष्ट करने वाला है। यह बजट बहुराष्ट्रीय कंपनियों को केवल रेड कार्पेट देता है। यह बजट सलाम करता है आॅर्थर डंकल को, यह बजट झुक कर चलता है डब्ल्यू०टी०ओ० और आई०एम०एफ० के सामने, यह बजट साम्राज्यवाद का दस्तावेज है। यह बजट पारित तो हो जाएगा पर इसके परिणाम बहुत भयानक आयेंगे।

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): बहुत-बहुत धन्यवाद डा० महेश चन्द्र शर्मा जी।

Hon. Members, there is a message from Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The National Environment Appellate Authority Bill, 1997

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the National Environment Appellate Authority Bill, 1997, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 17th March, 1997."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI) : We will take up the Budget. Shri Sanjay Nirupam—not present.

The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 18th March, 1997.

137/MP/RSS/ND/98—300 Copies—January 99—MGITBPChdg.